

आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश

हैदराबाद

बनाम

तोशोकू लिमिटेड, गुंटूर इत्यादि

29 अगस्त, 1980

[पी. एन. भगवती और ई.एस. वेंकटरमैया, जे.जे.]

सांविधिक अभिकर्ता द्वारा गैर-निवासी विदेशी अभिकर्ता को देय कमीशन – सांविधिक अभिकर्ता विदेशी अभिकर्ता से बिक्री मूल्य की प्राप्ति पर और उसके बाद विदेशी अभिकर्ता को कमीशन राशि भेजने पर "कमीशन खाता" शीर्षक के तहत अपने खाते की किताबों में क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टियां करता है- -क्या भेजी गई कमीशन राशि आयकर के निर्धारण योग्य थी -आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5(2), 9(1)(i), 160, 161 और 163 के लिए आकलन योग्य थी, जिसे बोर्ड के परिपत्र (XXVII-I)/1953 संख्या 26 (II/53) दिनांक 17 जुलाई, 1953 के साथ पढ़ा गया था -क्या राशियों को भारत में अर्जित या उत्पन्न हुई समझी गई आय माना जाना चाहिए।

विशेष अनुमति द्वारा राजस्व अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: (1) किसी वैधानिक अभिकर्ता की पुस्तकों में की गई क्रेडिट प्रविष्टियाँ अपने आप में गैर-निवासी निर्धारितियों द्वारा प्राप्त की गई राशि नहीं होती हैं, जब तक कि उनके पक्ष में जमा की गई राशियाँ उनके निपटान या नियंत्रण में नहीं होती हैं। [592 एफ]

इस मामले में गैर-निवासी निर्धारितियों को वैधानिक अभिकर्ता के साथ उनके खातों में जमा होने पर न तो प्रश्नगत राशि प्राप्त हुई और न ही प्राप्त हुई मानी जा सकती है, क्योंकि इससे अधिक के बिना क्रेडिट शेष केवल एक ऋण का प्रतिनिधित्व करता है और देनदार के स्वयं में केवल एक पुस्तक प्रविष्टि है। बही-खाते में वह भुगतान शामिल नहीं है जो ऋण से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। इसलिए, प्रासंगिक लेखांकन अवधि के दौरान कर योग्य क्षेत्रों में वास्तविक या रचनात्मक आय की प्राप्ति के आधार पर उन पर कर नहीं लगाया जा सकता है। [592 एफ-जी]

पी. वी. राघव रेड्डी और अन्य बनाम आयकर आयुक्त [1962] पूरक 2 एससीआर 596, विशिष्ट।

(2) आयकर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण के खंड (ए) के तहत। ऐसे व्यवसाय के मामले में जिसके सभी संचालन भारत में नहीं किए जाते हैं, उस खंड के तहत भारत में अर्जित या उत्पन्न होने वाली समझी जाने वाली व्यवसाय की आय, आय का केवल इतना हिस्सा होगी जो कि भारत में किए गए कार्यों के लिए उचित रूप से जिम्मेदार है। यदि ऐसे सभी ऑपरेशन भारत में किए जाते हैं, तो उनसे

होने वाली पूरी आय भारत में अर्जित मानी जाएगी। हालाँकि, यदि सभी परिचालन कर योग्य क्षेत्रों में नहीं किए जाते हैं, तो भारत में व्यापार कनेक्शन के माध्यम से और भारत में अर्जित समझे जाने वाले व्यापार के लाभ और लाभ केवल ऐसे लाभ और लाभ होंगे जो उचित रूप से कर योग्य क्षेत्रों में किए गए संचालन में उस हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। यदि कर योग्य क्षेत्रों में व्यवसाय का कोई संचालन नहीं किया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत में किसी भी व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से या उससे विदेश में अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय को भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं माना जा सकता है। [593 बी-डी]

वर्तमान मामले में गैर-निवासी निर्धारितियों ने कर योग्य क्षेत्रों में कोई भी व्यावसायिक संचालन नहीं किया। उन्होंने भारत के बाहर बिक्री अभिकर्ता के रूप में काम किया। विदेश से खरीददारों द्वारा भेजी गई या भेजी गई तम्बाकू की बिक्री आय की भारत में प्राप्ति भारत में निर्धारिती द्वारा किए गए ऑपरेशन के बराबर नहीं है, जैसा कि अधिनियम के धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण के खंड (ए) में माना गया है। इसलिए, भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए गैर-निवासी निर्धारितियों द्वारा अर्जित की गई कमीशन राशि को वह आय नहीं माना जा सकता है जो या तो भारत में अर्जित हुई है या उत्पन्न हुई है। [593 ई-जी]

आय-कर आयुक्त, पंजाब बनाम बनाम आर. डी. अग्रवाल एंड कंपनी और अन्य, 56, आई. टी. आर. 20 और मैसर्स कार्बोरेंडम कं. बनाम

सी. आई. टी. मद्रास [1977] 3 एस. सी. आर 475 , संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 782-783/1973

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित मामला संख्या 50 और 52/1970 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18-11-1972 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

पी. ए. फ्रांसिस, के. सी. दुआ और सुश्री ए. सुभाशिनी, अपीलार्थी की और से।

एल. ए. सुब्बा राव, प्रतिवादी की और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

वेंकटरमैया, न्यायाधिपति.-

विशेष अनुमति द्वारा ये दो अपीलें आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा 18 नवंबर, 1971 के एक संदर्भित मामला संख्या 50 और 52/1970 में पारित सामान्य फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

श्री बोम्मिडाला कोटिरत्नम (बाद में 'वैधानिक अभिकर्ता' के रूप में संदर्भित) आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर में तंबाकू का एक व्यापारी हैं। मूल्यांकन वर्ष 1962-63 से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान, वैधानिक अभिकर्ता ने भारत में तंबाकू खरीदा और इसे जापान में निर्यात किया, जहां इसे मेसर्स तोशोकू लिमिटेड, निर्धारिती सिविल अपील संख्या

782/1973 में एक जापानी कंपनी में शामिल था और स्वीकार्य रूप से अनिवासी था, के माध्यम से बेचा गया था। । वैधानिक अभिकर्ता और ऊपर उल्लिखित करदाता के बीच समझौते की शर्तों के तहत, करदाता को पूर्व द्वारा निर्यात किए गए तंबाकू की बिक्री के लिए जापान में विशेष बिक्री अभिकर्ता नियुक्त किया गया था। निर्धारिती चालान राशि के 3% कमीशन का हकदार था। जापान में तम्बाकू की बिक्री पर प्राप्त बिक्री मूल्य पूरी तरह से वैधानिक अभिकर्ता को भेज दिया गया था, जिसने जापानी कंपनी को देय कमीशन की राशि के साथ अपने कमीशन खाते को डेबिट किया था और 31 दिसंबर 1961 को अपनी पुस्तकों में जापानी कंपनी के खाते में इसे जमा किया था। यह राशि जापानी कंपनी को 1 फरवरी, 1962 को भेजी गई थी, जिस तारीख को वैधानिक अभिकर्ता के साथ जापानी कंपनी के खाते में एक उचित डेबिट प्रविष्टि की गई थी।

वैधानिक अभिकर्ता ने उसी लेखांकन अवधि के दौरान मेसर्स सोसाइटी पौर ले कॉमर्स इंटरनेशनल डेस टोबैक्स (सिविल अपील संख्या 783/1973 की में शामिल निर्धारिती) नाम के एक अन्य गैर-निवासी व्यापारिक घराने के माध्यम से कुछ तंबाकू बेचा था, जो फ्रांस में व्यापार कर रहा था। समझौते की शर्तें वही थीं जो ऊपर उल्लिखित जापानी कंपनी के मामले में थीं, अंतर केवल भौगोलिक क्षेत्र का था जिसमें उनमें से प्रत्येक को बिक्री अभिकर्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी थी। इस मामले में भी वैधानिक-अभिकर्ता ने निर्धारिती को देय कमीशन के संबंध में अपनी

पुस्तकों में समान प्रविष्टियां कीं और अंततः जब राशि निर्धारिती को प्रेषित की गई तो उसने अपनी पुस्तकों में निर्धारिती के खाते में डेबिट प्रविष्टि की।

मूल्यांकन वर्ष के दौरान यह प्रश्न कि क्या जापानी कंपनी और फ्रांसीसी बिजनेस हाउस (बाद में सामूहिक रूप से 'करदाता' के रूप में संदर्भित) को भेजी गई कमीशन राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 161 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के संदर्भ में मूल्यांकन योग्य थी, आयकर अधिकारी के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। वैधानिक अभिकर्ता ने तर्क दिया कि 17 जुलाई, 1953 के बोर्ड परिपत्र (XXVII-I) 53 नंबर 26 (II/53) द्वारा कानूनी स्थिति के स्पष्टीकरण के मद्देनजर विचाराधीन राशि कर योग्य नहीं थी, जिसमें कहा गया था:

"एक भारतीय निर्यातक का विदेशी अभिकर्ता अपने ही देश में काम करता है और उसकी आय का कोई भी हिस्सा भारत में नहीं आता है। आमतौर पर उसका कमीशन सीधे उसे भेज दिया जाता है और इसलिए भारत में उसकी ओर से या उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। ऐसा अभिकर्ता भारतीय आयकर के प्रति उत्तरदायी नहीं है।"

हालांकि, आयकर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पी.वी.राघव रेड्डी और अन्य बनाम आयकर आयुक्त [1962] पूरक 2 एससीआर 596 के मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर विचाराधीन रकम कर योग्य थी और धारा 143(3) के तहत उनका मूल्यांकन किया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 163 के अपीलीय सहायक आयुक्त और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मूल्यांकन के आदेशों के खिलाफ वैधानिक अभिकर्ता द्वारा की गई अपील असफल रही। इसके बाद कानून के निम्नलिखित सामान्य प्रश्न को अधिनियम की धारा 256(1) के तहत आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को भेजा गया था।

" क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 161 के तहत अपीलार्थी पर निर्धारण उचित है? "

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आकलन उचित नहीं थे और विभाग के खिलाफ सवाल का जवाब दिया। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत ये अपीलें।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान जिन पर निर्भरता हमारे सामने रखी गई है वे धारा 5(2), 9(एल)(i), 160, 161 और 163 हैं। अधिनियम की धारा 5(2) जो अधिनियम के तहत गैर-निवासी व्यक्ति की आय की प्रभार्यता से संबंधित है, यह प्रावधान करती है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय एक गैर-निवासी में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय शामिल होती है (ए) जो ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया गया माना जाता है, या (बी) ऐसे वर्ष के दौरान भारत में अर्जित या उत्पन्न होता है या अर्जित या उत्पन्न माना जाता है। अधिनियम की धारा 5(2) का स्पष्टीकरण 1 घोषित करता है कि विदेश में

उत्पन्न होने वाली आय को केवल इस कारण से उस धारा के प्रयोजन के लिए भारत में प्राप्त नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह भारत में तैयार की गई बैलेंस शीट में शामिल है। अधिनियम की धारा 9(1)(i) में प्रावधान है कि भारत में किसी भी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से या उससे, या भारत में किसी भी संपत्ति के माध्यम से या उससे, या किसी संपत्ति या स्रोत के माध्यम से या उससे उत्पन्न होने वाली सभी आय। भारत में आय, या भारत में स्थित पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाएगी। इस खंड की व्याख्या यह प्रदान करती है कि ऐसे व्यवसाय के मामले में जिसके सभी संचालन भारत में नहीं किए जाते हैं, इस खंड के तहत भारत में अर्जित या उत्पन्न होने वाली समझी जाने वाली व्यवसाय की आय आय का केवल इतना हिस्सा होगी। भारत में किए गए परिचालनों के लिए उचित रूप से जिम्मेदार है और गैर-निवासी के मामले में कोई भी आय उन परिचालनों के माध्यम से या उनसे भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाएगी जो निर्यात के उद्देश्य से भारत में माल की खरीद तक ही सीमित हैं। एक गैर-निवासी का अभिकर्ता जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे अधिनियम की धारा 163 के तहत अभिकर्ता माना जाता है, अधिनियम की धारा 160(1) के अनुसार, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनिवासी की आय के संबंध में प्रतिनिधि निर्धारिती बन जाता है। अधिनियम की धारा 161 एक प्रतिनिधि निर्धारिती, जो एक अनिवासी का अभिकर्ता है, को अनिवासी की आय के संबंध में मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाती है।

अधिनियम की धारा 163 उन व्यक्तियों को परिभाषित करती है जिन्हें अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गैर-निवासियों के अभिकर्ता के रूप में माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 160, 161 और 163 केवल सक्षम प्रावधान हैं जो अधिकारियों को प्रतिनिधि निर्धारिती से अधिनियम के तहत कर का आकलन करने और उसकी वसूली करने के विकल्प का अधिकार देते हैं। इन मामलों में यह विवादित नहीं है कि यदि निर्धारिती की आय कर योग्य है, तो वैधानिक अभिकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वास्तविक प्रश्न जो निर्धारण के लिए है वह यह है कि क्या उक्त आय कर योग्य है। इन अपीलों में पाए गए तथ्य यह हैं कि वैधानिक अभिकर्ता ने अपना माल जापान और फ्रांस को निर्यात किया जहां उन्हें निर्धारितियों के माध्यम से बेचा गया। संपूर्ण बिक्री मूल्य भारत में वैधानिक अभिकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसने निर्धारितियों को देय कमीशन राशि के संबंध में अपनी खाता पुस्तकों में क्रेडिट प्रविष्टियां कीं और बाद में उन्हें कमीशन राशि भेज दी। जापानी कंपनी के मामले में एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि इसे जापान के लिए एक विशेष अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। यह विवादित नहीं है कि निर्धारितियों ने कर योग्य क्षेत्रों के बाहर वैधानिक अभिकर्ता को विक्रय एजेंट के रूप में सेवा प्रदान की।

अपना मामला स्थापित करने के लिए, राजस्व ने पी.वी.राघव रेड्डी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया है

उस निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त मामला तथ्यों के आधार पर अलग है। उस मामले में निर्धारिती ने वर्ष 1948-49 और 1949-50 में कुछ मात्रा में अभ्रक जापान को निर्यात किया था। उन वर्षों के दौरान अभ्रक सीधे जापानी खरीदारों को निर्यात योग्य नहीं था क्योंकि जापान सैन्य कब्जे में था, लेकिन बोएकी-चो (व्यापार बोर्ड) नामक एक राज्य संगठन को निर्यात किया जा सकता था। ऑर्डर के लिए बातचीत करने और उसके संबंध में जापान में इसके अन्य मामलों को संभालने के लिए निर्धारिती ने सैन-ईई ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, टोक्यो को अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया। जापानी कंपनी निश्चित रूप से एक 'गैर-अनिवासी' कंपनी थी। समझौतों के तहत निर्धारिती ने जापानी कंपनी को कमीशन के रूप में सकल बिक्री आय का कुछ प्रतिशत भुगतान करने का वचन दिया। कमीशन के भुगतान के तरीके के संबंध में, समझौतों में एक शब्द प्रदान किया गया है जो इस प्रकार है:

"इस देश में कठिनाइयों को देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि प्रथम पक्ष इन सभी राशियों को दूसरे पक्ष के खाते में बिना जमा किए तब तक जमा कर दे जब तक कि प्रथम पक्ष को निश्चित निर्देश प्राप्त न हो जाएं"

करार का प्रथम प्रक्षर निर्धारिती था और दूसरा पक्षकार जापानी कंपनी थी। दो लेखांकन वर्षों के दौरान, जापानी कंपनी को कुल 13,319,124 रुपये का भुगतान या तो सीधे या दूसरों के माध्यम से किया गया था,

जिन्हें जापानी कंपनी द्वारा निर्धारिती को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने निर्धारिती के निम्नलिखित अवलोकन इस तर्क को खारिज कर दिया कि जापानी कंपनी को कर योग्य क्षेत्रों में राशि प्राप्त नहीं हो रही थी और यह राशि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 4 (एल) (ए) के अर्थ के तहत आय नहीं थी:-

" यह उस प्रश्न को छोड़ देता है जिस पर ईमानदारी से तर्क दिया गया था, अर्थात्, क्या दो लेखांकन वर्षों में रकम को जापानी कंपनी द्वारा कर योग्य क्षेत्रों में प्राप्त किया जा सकता है। तर्क यह है कि पैसा वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन निर्धारिती फर्म उस राशि के संबंध में देनदार थी और जब तक प्रविष्टि को भुगतान या रसीद नहीं माना जा सकता तब तक खंड (ए) लागू नहीं हो सकता। हमें कल्पना पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल्पना में जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। समझौता, जिसमें से हमने प्रासंगिक शब्द उद्धृत किया है, बशर्ते कि जापानी कंपनी चाहती थी कि निर्धारिती फर्म को अपने खाते की किताबों में जापानी कंपनी के नाम पर एक खाता खोलना चाहिए, खाते में राशि जमा करनी चाहिए, और सौदा करना चाहिए जापानी कंपनी के निर्देशों के अनुसार उन राशियों के साथ। जब तक पैसा जमा नहीं किया गया, तब तक देनदार और लेनदार का संबंध हो सकता है; लेकिन रकम जमा होने के बाद, पैसा निर्धारिती फर्म द्वारा जमाकर्ता के रूप में रखा गया था। तब पैसा जापानियों, कंपनी का था और कंपनी के लिए और उसकी ओर से

रखा गया था और उसके निपटान में था। धन का चरित्र ऋण से जमा में उसी तरह बदल गया जैसे वह बैंक में कंपनी के खाते में जमा किया गया हो। इस प्रकार, समझौते की शर्तों के अनुसार, राशि को जापानी कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, और यह धारा 4(1)(ए) के आवेदन को आकर्षित करता है। वास्तव में, जापानी कंपनी ने निर्धारित फर्म को यह निर्देश देकर उन राशियों के एक हिस्से का निपटान किया कि उन्हें एक विशेष तरीके से लागू किया जाए। हमारी राय में, उच्च न्यायालय गधों के विरुद्ध प्रश्न का उत्तर देने में सही था।”

न्यायालय, जैसा कि ऊपर दिए गए अंश से स्पष्ट है, यह मानने के लिए आगे बढ़ा कि विचाराधीन राशि भारत में जापानी कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी और इसलिए उस आधार पर कर योग्य थी।

हमारे सामने आए मामलों में ऊपर निकाले गए शब्दों के अनुरूप कोई शर्तें नहीं थीं जो कि पी.वी. राघव रेड्डी का मामला (उपरोक्त) में निर्धारित और जापानी कंपनी के बीच हुए समझौतों में पाई गई थीं। यह नहीं कहा जा सकता है कि वैधानिक अभिकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टियां उन निर्धारितियों द्वारा प्राप्त की गईं जो गैर-निवासी थे क्योंकि उनके पक्ष में जमा की गई राशि उनके निपटान या नियंत्रण में नहीं थी। यह मानना संभव नहीं है कि इस मामले में गैर-निवासी निर्धारितियों को वैधानिक अभिकर्ता के खातों में जमा होने पर प्रश्नगत रकम या तो प्राप्त हुई या प्राप्त हुई मानी जा सकती है, क्योंकि इससे अधिक के बिना क्रेडिट शेष केवल

ऋण का प्रतिनिधित्व करता है और देनदार की अपनी पुस्तकों में केवल बही प्रविष्टि से भुगतान नहीं हो जाता जिससे ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए, प्रासंगिक लेखांकन अवधि के दौरान कर योग्य क्षेत्रों में वास्तविक या रचनात्मक आय की प्राप्ति के आधार पर उन पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

इसी प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि क्या वैधानिक एजेंट की पुस्तकों में जमा की गई कमीशन राशि को संबंधित वर्ष के दौरान अनिवासी निर्धारितियों के लिए भारत में अर्जित, उत्पन्न, या अर्जित या उत्पन्न हुई आय के रूप में माना जा सकता है। यह हमें अधिनियम की धारा 9 तक ले जाता है। यह आग्रह किया जाता है कि कमीशन राशि को भारत में अर्जित या उत्पन्न हुई समझी जाने वाली आय के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि विभाग के अनुसार, वे या तो भारत में अनिवासी करदाताओं और के बीच मौजूद व्यापार कनेक्शन के माध्यम से अर्जित या उत्पन्न हुई थीं। वैधानिक एजेंट. यह विवाद स्पष्टीकरण के खंड (ए) के प्रभाव को नजरअंदाज करता है अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) का खंड (i) जो यह प्रावधान करता है कि ऐसे व्यवसाय के मामले में जिसके सभी संचालन भारत में नहीं किए जाते हैं, उस खंड के तहत व्यवसाय की आय अर्जित या अर्जित मानी जाएगी भारत में उत्पन्न होने वाली आय का केवल उतना हिस्सा होगा जो भारत में किए गए कार्यों के लिए उचित रूप से जिम्मेदार है। यदि ऐसे सभी ऑपरेशन भारत में

किए जाते हैं, तो उनसे होने वाली पूरी आय भारत में अर्जित मानी जाएगी। हालाँकि, यदि सभी परिचालन कर योग्य क्षेत्रों में नहीं किए जाते हैं, तो भारत में व्यापार कनेक्शन के माध्यम से और भारत में अर्जित समझे जाने वाले व्यापार के लाभ और लाभ केवल ऐसे लाभ और लाभ होंगे जो उचित रूप से उस हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। कर योग्य क्षेत्रों में किए गए संचालन। यदि कर योग्य क्षेत्रों में व्यवसाय का कोई संचालन नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि भारत में किसी भी व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से या विदेश में अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय को भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं माना जा सकता है। (देखें आयकर आयुक्त, पंजाब बनाम आर.डी.अग्रवाल एंड कंपनी और अन्य 56, आई.टी.आर. 20 और मैसर्स कार्बोरेडम कंपनी बनाम सी.आई.टी. मद्रास [1977] 3 एस.सी.आर 475], जो भारतीय आय कर अधिनियम 1922 की धारा 42 के आधार पर तय किए गए हैं, जो अधिनियम की धारा 9(1)(i) से मेल खाता है।)

वर्तमान मामले में गैर-निवासी निर्धारितियों ने कर योग्य क्षेत्रों में कोई भी व्यावसायिक संचालन नहीं किया। उन्होंने भारत के बाहर बिक्री अभिकर्ता के रूप में काम किया। विदेश से खरीददारों द्वारा भेजे गए या भेजे जाने वाले तंबाकू की बिक्री आय की भारत में प्राप्ति भारत में निर्धारिती द्वारा किए गए ऑपरेशन के बराबर नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण के खंड (ए) में माना गया है। इसलिए,

भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनिवासी निर्धारितियों द्वारा अर्जित की गई कमीशन राशि को वह आय नहीं माना जा सकता है जो या तो भारत में अर्जित हुई है या उत्पन्न हुई है। इसलिए, विभाग के खिलाफ सवाल का जवाब देने में उच्च न्यायालय सही था।

पूर्वगामी कारणों से, अपील विफल हो जाती हैं और एतद्वारा लागतों के साथ खारिज की जाती हैं। (सुनवाई शुल्क एक सेट)।

वी.डी.के.

याचिकाएं खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।
